



14 मिनट	8	24	1	GS1 • 6	GS2 • 28	GS3 • 24
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	मेन्स प्रश्न	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 Census 2027: भारत ने Questionnaire को बढ़ाकर 40 किया, 29 श्रेणियों के अलावा Caste को भी जोड़ा

क्यों ज़रूरी: जनगणना 2027 अपने प्रश्नावली का विस्तार कर 40 प्रश्नों तक करेगी, जिसमें पिछले 29 श्रेणियों के अतिरिक्त अब सभी उत्तरदाताओं से जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने का प्रावधान शामिल है।

GS1 • भारतीय समाज

P

M

2 Census में बड़ा बदलाव: मोदी ने सभी उत्तरदाताओं के लिए जाति जनगणना को मंजूरी दी

क्यों ज़रूरी: भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना पद्धति में एक व्यापक बदलाव की अधिसूचना जारी की है, जिसमें सभी उत्तरदाताओं के लिए पूर्ण जाति गणना शामिल है।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

3 मोदी ने Independence Day स्पीच में 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा

क्यों ज़रूरी: प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में भारत के ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के उद्देश्य से वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य घोषित किया।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

4 टैक्सपेयर्स को मिलेगी छूट: छिपी हुई विदेशी संपत्ति पर I-T डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया 60% टैक्स FAST-DS

क्यों ज़रूरी: आयकर विभाग ने लघु करदाताओं को अभियोजन से छूट के बदले अपनी छिपी हुई विदेशी संपत्तियों को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु FAST-DS योजना शुरू की है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

5 सीक्रेट मीटिंग में पुतिन ने रूस को NATO और EU को अंदर से टारगेट करने का दिया आदेश

क्यों ज़रूरी: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रूस, मोल्दोवा पर अधिकार करने के साथ-साथ NATO और EU को आंतरिक रूप से अस्थिर करने के लिए एक द्वि-स्तरीय रणनीति (dual-track strategy) की योजना बना रहा है।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

GS1 · भारतीय समाज

P

M

Census 2027: भारत ने Questionnaire को बढ़ाकर 40 किया, 29 श्रेणियों के अलावा Caste को भी जोड़ा

चर्चा में क्यों: जनगणना 2027 अपने प्रश्नावली का विस्तार कर 40 प्रश्नों तक करेगी, जिसमें पिछले 29 श्रेणियों के अतिरिक्त अब सभी उत्तरदाताओं से जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने का प्रावधान शामिल है।

याद रखें

- Census 2027 प्रश्नावली का विस्तार कर 40 प्रश्नों तक कर दिया गया है।
- स्वतंत्रता के बाद पहली बार सभी उत्तरदाताओं से जाति संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी।
- नई प्रणाली पिछले 29 जाति श्रेणियों से आगे बढ़कर एक ओपन-कॉलम दृष्टिकोण (open-column approach) अपनाती है।

मेन्स कोण भारत में समावेशी नीति-निर्माण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में जनगणना में व्यापक जातिगत डेटा संग्रह के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/104718

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

Census में बड़ा बदलाव: मोदी ने सभी उत्तरदाताओं के लिए जाति जनगणना को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों: भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना पद्धति में एक व्यापक बदलाव की अधिसूचना जारी की है, जिसमें सभी उत्तरदाताओं के लिए पूर्ण जाति गणना शामिल है। इस प्रस्ताव को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

याद रखें

- Census Act, 1948: भारत में जनगणना के संचालन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Registrar General of India: जनगणना और जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण।
- पूर्ण जाति गणना: केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों की गणना से हटकर सभी उत्तरदाताओं को शामिल करने की ओर बदलाव।

मेन्स कोण भारत में समावेशी नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में जनगणना में व्यापक जातिगत गणना के महत्व पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/104302

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

मोदी ने Independence Day स्पीच में 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में भारत के ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के उद्देश्य से वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य घोषित किया।

याद रखें

- परमाणु ऊर्जा लक्ष्य: 2047 तक 100 GW।
- AI प्रशिक्षण लक्ष्य: 1 करोड़ युवा।
- सेमीकंडक्टर विनिर्माण विस्तार पर ध्यान केंद्रित करें।

मेन्स कोण भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों की प्राप्ति में परमाणु ऊर्जा के महत्व और वर्ष 2047 तक परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/104802

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

टैक्सपेयर्स को मिलेगी छूट: छिपी हुई विदेशी संपत्ति पर I-T डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया 60% टैक्स FAST-DS

चर्चा में क्यों: आयकर विभाग ने लघु करदाताओं को अभियोजन से छूट के बदले अपनी छिपी हुई विदेशी संपत्तियों को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु FAST-DS योजना शुरू की है।

याद रखें

- आयकर विभाग: भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी।
- FAST-DS योजना: स्वैच्छिक प्रकटीकरण (voluntary disclosure) के लिए प्रभावी कर दर 60% है।
- FAST-DS योजना: प्रकटीकरण की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2026 तक खुली है।

मेन्स कोण भारत में FAST-DS जैसी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं (voluntary disclosure schemes) किस प्रकार कर अनुपालन को बढ़ाने और धन शोधन (money laundering) को रोकने में सहायक हो सकती हैं, इस पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/105186

सीक्रेट मीटिंग में पुतिन ने रूस को NATO और EU को अंदर से टारगेट करने का दिया आदेश

चर्चा में क्यों: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रूस, मोल्दोवा पर अधिकार करने के साथ-साथ NATO और EU को आंतरिक रूप से अस्थिर करने के लिए एक द्वि-स्तरीय रणनीति (dual-track strategy) की योजना बना रहा है।

याद रखें

- NATO: North Atlantic Treaty Organization, एक सामूहिक रक्षा गठबंधन।
- मोल्दोवा: पूर्वी यूरोप का एक भू-आबद्ध (landlocked) देश जो रोमानिया, यूक्रेन और ब्लैक सी (Black Sea) की सीमाओं से घिरा है।
- रूस ने यूक्रेन के जलविद्युत संयंत्रों पर हमले किए हैं, जिससे मोल्दोवा के जल और बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

मेन्स कोण हाइब्रिड युद्ध और बुनियादी ढाँचे की तोड़फोड़ (इन्फ्रास्ट्रक्चर सबोटेज) के यूरोपीय सुरक्षा और नाटो (NATO) के सामूहिक रक्षा तंत्र पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/104890

राज्यसभा ने खनन पर राज्यों द्वारा टैक्स लगाने पर रोक लगाने वाला संशोधन पास किया

चर्चा में क्यों: राज्यसभा ने राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, खनन कार्यों पर राज्यों द्वारा कर या उपकर लगाने पर रोक लगाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में एक संशोधन पारित किया।

याद रखें

- Mines and Minerals (Development and Regulation) Act भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- यह संशोधन राज्यों को खनिजों और खनन कार्यों पर कर या उपकर (cess) लगाने से रोकता है।
- ओडिशा और झारखंड को भारत के प्रमुख खनिज-संपन्न राज्यों के रूप में पहचाना गया है।

मेन्स कोण खनन कार्यों पर राज्य करों को प्रतिबंधित करने वाले केंद्रीय विधान के सहकारी संघवाद और राजकोषीय स्वायत्तता के सिद्धांत पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/104823

माउंटबेटन योजना और उसके पश्चात पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को भारत के विभाजन के लिए आधारभूत कानूनी और राजनीतिक ढाँचे के रूप में रेखांकित किया गया है

चर्चा में क्यों: माउंटबेटन योजना और उसके पश्चात पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को भारत के विभाजन के लिए आधारभूत कानूनी और राजनीतिक ढाँचे के रूप में रेखांकित किया गया है।

याद रखें

- लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 वह विधायी उपकरण था जिसने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया।
- माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव 3 जून, 1947 को दिया गया था।

मेन्स कोण माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने भारतीय उपमहाद्वीप के भू-राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को किस प्रकार आकार दिया, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/104827

Maddison Project Database 2023 के मुताबिक भारत की GDP per capita में गिरावट

चर्चा में क्यों: मैडिसन प्रोजेक्ट डेटाबेस 2023 भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी (GDP) के दीर्घकालिक प्रक्षेपवक्र को रेखांकित करता है, जो औपनिवेशिक इतिहास और 1990 के दशक के बाद के सुधारों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

याद रखें

- 1940 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP वैश्विक औसत का 32% थी।
- वर्ष 2026 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर 6.4% है।
- Maddison Project Database ऐतिहासिक GDP डेटा के लिए एक प्राथमिक स्रोत है।

मेन्स कोण औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी (GDP per capita) में आए ठहराव के कारकों का विश्लेषण कीजिए और इसमें 1990 के दशक के सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/104643

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

भारत के 80 साल पूरे, लाल किले से पहली बार गाया वंदे मातरम

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिकी विदेश विभाग तकनीकी वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए 35 देशों पर अमेरिका के नेतृत्व वाल

भारत और रूस ने NSR के जरिए रणनीतिक आर्कटिक रूट पर गहरे सहयोग पर चर्चा की

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने TV चैनलों के लिए 12-minute एड कैप हटाया

चीन से मुकाबला करने की होड़: Fujian के 2026 तक तैयार होने से पहले IAC-2 के अप्रूवल का इंतज़ार

कर्नाटक के परिवहन मंत्री ने 15,000 नई बसें और 10 लाख छात्रों के लिए फ्री पास की घोषणा की

शिक्षा में बदलाव के लिए आंध्र प्रदेश ने 29 टॉप टीचर्स को फिनलैंड भेजा

ट्राइबल म्यूजिशियन नंजीम्मा को नेशनल अवॉर्ड, कॉपीराइट पहल को मिली मजबूती

आंध्र प्रदेश मना रहा है स्त्री शक्ति वर्ष – डबल डिग्लिटी एनिवर्सरी

मद्रास हाई कोर्ट में तमिल थाई वझु शुरू करने पर प्रोटोकॉल को लेकर विवाद

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

मोदी ने 1 करोड़ युवाओं के लिए AI ट्रेनिंग और 10 million बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हंट का किया ऐलान

RBI ने 31 अगस्त के पश्चात नए संग्रहण हेतु FCNR(B) जमा के लिए स्वैप सुविधा को बंद करने की घोषणा की है, जो विदेशी मुद्रा जमा प्रबंधन को प्रभावित करेगा

PM Narendra Modi ने लाल किले पर 'Sapta Dhara' फ्रेमवर्क का अनावरण किया

सुप्रीम कोर्ट ने कुकी और मैतेई गुप्स से मणिपुर हाईवे से बैरिकेड्स हटाने की अपील की

डिफेंस बजट ₹7.85 लाख करोड़ पहुंचा, R&D में 90% की बढ़ोतरी: Rajnath Singh

Indian Army को ₹1,577 करोड़ की 'Buy Indian' डील में मिले 84 loiter munition systems

CAG की रिपोर्ट ने 'ग्रीन इंडिया मिशन' (GIM) के वन आच्छादन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण कमी को र

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के

ट्रिब्यूनल ने TNPCB को नेवेली में मरकरी लेवल पर कार्रवाई का आदेश दिया

ड्रोन से उम्मीद की नई किरण: HML ने पीरूमडे पहाड़ियों के पास 15 एकड़ में 24 देशी प्रजातियों के बीज बोए

राष्ट्रपति ने Independence Day पर 9 Kirti Chakras समेत 78 Gallantry Awards को दी मंजूरी

BCG वैक्सीन से बूढ़े इम्यून सेल्स को मिलेगी नई ट्रेनिंग, Alzheimer's के इलाज के लिए उम्मीद

'नेचर' (Nature) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2060 तक फोटोवोल्टिक (PV) कचरे में भ

पर्यटन और संस्कृति मंत्री Kandula Durgesh ने ₹2,643 के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की

GS1 • भारतीय समाज

भारत में समावेशी नीति-निर्माण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में जनगणना में व्यापक जातिगत डेटा संग्रह के महत्व पर चर्चा कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह **टेलीग्राम** पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।